



12/01/81
12/01/81

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]
No. 34]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1981/माघ 1, 1902
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1981/MAGHA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

का० आ० 43 (प्र) /18-ब/उ० वि० आ०/80.—केन्द्रीय सरकार
ने उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65)
की धारा 18-ब की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक
विकास विभाग) के आदेश सं. का० आ० 39(प्र) /18-ब/उ० वि० आ०/77, तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसमें इसके पाण्डात् उक्त
आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि:—

(क) प्रौद्योगिक विकास प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14),
हन अनुकूलतों सहित कि उक्त प्रधिनियम की धारा 9-क के
प्रधार्य 5-क और 5-ख और धारा 33-ग का लोप किया जाएगा,
मैसर्स बगाल पाटीर निमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन वा
प्रौद्योगिक उपकरणों को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की नारीक में ठोक पूर्व प्रदून
ऐसी मधी संविधानों, सम्मति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों,
व्यवस्थापनों, पंचांत्रों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन
(उनसे भिन्न जिनका सम्बन्ध वैकों और विसीय सत्याक्रों के

प्रतिभूत विधियों से हैं) जिनके उक्त अधिकारिक उपकरण पक्ष-
कार हैं या ऐसे अधिकारिक उपकरणों की स्वामी कानूनी पक्षकार
हैं या जो यास्तिति, उन अधिकारिक उपकरणों वा कानूनी को
लागू होते हैं, और उक्त तारीख के पूर्व उनके प्रधीन, प्रदून
या उद्भूत सभी या कोई प्रधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं
और वायित्व नियमित रहेंगे,

और उक्त आदेश की प्रवधि को ममय-समय पर 21 जनवरी,
1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए
बड़ा बिया जाना चाहिए,

प्रीत केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश
की प्रवधि को 14 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख
भी सम्मिलित है, की अनिरिक्त प्रवधि के बिंदु बदाया जाना
चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास प्रौद्योगिक विनियमन) प्रधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18-ब की उपधारा (2) के साथ
पिल उपधारा (1) के खण्ड (क) प्रौद्योगिक उपकरणों का
प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की प्रवधि को 14 सितम्बर, 1981 तक,
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बड़ाती है।

[का० सं. 2(4)/80-सी० य० सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 21st January, 1981

S.O. 43 (E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39 (E)/18FB/ IDRA/77 dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that,—

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 9A, Chapters VA and VB and section 33 C of the said Act shall be omitted, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial undertakings or the company, as the case be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing thereunder before the said date shall remain suspended ;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 21st January, 1981;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 14th September, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extend the duration of the said Order upto and inclusive of the 14th September, 1981.

[File No. 2(4)/80-CUC]

प्रावेश

का० आ० 44(भ).—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रादेश सं० का० आ० 426(भ)/18क/उ०वि०वि०प्र०/74, नारोब० 8 जुलाई, 1974 द्वारा व्यासम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को मैसमं एम्सिमिटेड इण्स्ट्रीज (असम) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपकरण के (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपकरण के इप में मिनिट दिया गया है) रसायन एकक का उसमें विनिर्दिष्ट प्रवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 18क की उधारा (2) द्वारा प्रबन्ध ग्रहितयों का प्रयोग करने हुए इससे उपर्युक्त भूतपूर्वों में उन व्यापारों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं की विनिर्दिष्ट करती है जिनके प्रधीन रहते हुए कम्पनी प्रधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपकरण को उसी प्रकार लागू होता रहेगा जिस प्रकार वह धारा 18क के प्रधीन व्यावेश जारी किए जाने के पूर्व इसे लागू था ।

कम्पनी प्रधिनियम 1956 के प्रवदाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहने वाले स्थान (1) में उल्लिखित उपवध उक्त औद्योगिक उपकरण को लागू होंगे ।

(1)

(2)

धारा 166 और 210

यद्यपि कम्पनी का भूतन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा वायिक साधारण प्रधिवेशन के समक्ष रखा जाता जरूरी नहीं है क्योंकि उम्म प्रधिवेशन के दौरान जब कम्पनी का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन किया जाता है, ऐसा प्रधिवेशन किए जाने से छूट दी जा रही है फिर भी भूतन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा पहले की भाँति विहित समय के भीतर तैयार कराया जाएगा और प्रत्यक्ष कानूनी विवरणों के साथ-साथ कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास काइल किया जाएगा । इसमें व्यवहारों में, प्राधिकृत नियन्त्रक को, रजिस्ट्रार के पास भूतन-पत्र काइल करने के प्रयोजन के लिए धारा 220 का अनुपालन करना होगा ।

धारा 217

छूट के बाद इस सीमा तक अनुदत्त की जाती है कि बोर्ड की रिपोर्ट ऊपर लिखित कारणों से वायिक साधारण प्रधिवेशन के समय जब्ती जानी अनिवार्य नहीं होती किन्तु प्रत्यक्ष भूमि की वावत अनुपालन आवश्यक होगा ।

धारा 224 और 225

इन व्यावहारों के अनुपालन से, इस गति के अधीन रहने हुए छूट दी जाती है कि संपर्ककों की नियुक्ति सरकार धारा जिससे संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय अभिनेत है, की जाएगी ।

धारा 293(1)(घ)

इस धारा के अनुपालन से छूट दी जाती है ।

धारा 169 और 219

इस धारा के अनुपालन से छूट दी जाती है ।

[का० मं० 4(4)/80-सी० य० स०]

धारा० एन० बोपड़ा, अपर सचिव

S.O.44(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426 (E)/18AA/IDRA/74 dated the 8th July, 1974 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby authorise the Assam Industrial Development Corporation Limited, to take over the management of the Chemical Unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the said

industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

(1)

(2)

words section 220 shall have to be complied with by the authorised Controller for the purpose of filing the Balance Sheet with the Registrar.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking.	Section 217	words section 220 shall have to be complied with by the authorised Controller for the purpose of filing the Balance Sheet with the Registrar.
(1)	(2)		
Sections 166 and 210	While the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company need not be laid before the annual general meeting as the exemption is granted from such meetings during the period when the Company is managed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Balance Sheet and Profit and Loss Account may be prepared as usual within the prescribed time and shall be filed with the Registrar of Companies along with other statutory returns. In other	Sections 224 and 225	The exemption is granted only to the extent that Board's report is not required to be placed before the annual general meeting for the reasons stated above but compliance shall be necessary in all other respects.
		Section 293 (1)d	Exemption from the compliance of these sections is granted subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government which means the administrative Ministry concerned.
		Sections 169 and 219	Exemption is granted from compliance of these sections.
			Exemption is granted from compliance of these sections.

[F.No. 4(4)/80-CUC]

R.N.CHOPRA, Additional Secy.

